OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 3 Issue 4 [Jul- Aug] 2024*

I J C R M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

The Role of Regional Parties During the Era of Coalition Governments (1989–2014): A Study

गठबंधन सरकारों के दौर (1989-2014) में क्षेत्रीय दलों की भूमिका: एक अध्ययन

Dr. Ashok Kumar Meena

Assistant Professor, Political Science, Government College, Masalpur, Karauli, Rajasthan, India

Corresponding Author: * Dr. Ashok Kumar Meena

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21840818

Abstract

The period from 1989 to 2014 represents an epoch-making transitional phase in the history of Indian politics, generally referred to as the 'era of coalition politics' or 'the age of the multi-party system.' With the 9th General Election of 1989, the one-party dominance of the Indian National Congress formally came to an end, and regional political parties made a decisive entry into the centre of national politics. This research paper presents a multidimensional and analytical study of the role, influence, and strategic behaviour of regional parties in the various coalition governments formed at the Centre between 1989 and 2014.

The study highlights how, during the periods of the National Front (1989–1991), the United Front (1996–1998), the National Democratic Alliance (NDA: 1998–2004), and the United Progressive Alliance (UPA: 2004–2014), regional parties played the role of 'kingmaker' and policy-shapers. This paper examines the impact of regional aspirations on the discourse surrounding Indian federalism, foreign policy, economic reforms, and secularism versus communalism. The study concludes that although the excessive influence of regional parties sometimes gave rise to policy paralysis and political instability, it also lent Indian democracy a more inclusive, representative, and federal character.

वर्ष 1989 से 2014 का कालखंड भारतीय राजनीति के इतिहास में एक युगान्तकारी संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सामान्यतः 'गठबंधन राजनीति का युग' या 'बहुदलीय व्यवस्था का दौर' कहा जाता है। 1989 के 9वें आम चुनाव के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकदलीय प्रभुत्व (One-Party Dominance) का औपचारिक अंत हुआ और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का निर्णायक पदार्पण हुआ। प्रस्तुत शोध पत्र 1989 से 2014 के मध्य केंद्र में निर्मित विभिन्न गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, प्रभाव, और रणनीतिक व्यवहार का एक बहुआयामी एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

अध्ययन में यह रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रीय मोर्चा (1989-1991), संयुक्त मोर्चा (1996-1998), राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA: 1998-2004), तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA: 2004-2014) के दौर में क्षेत्रीय दलों ने 'किंगमेकर' और नीति-निर्धारक की भूमिका निभाई। यह पत्र भारतीय संघवाद विदेश नीति, आर्थिक सुधारों, और धर्मनिरपेक्षता-बनाम-सांप्रदायिकता के विमर्श पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रभाव का परीक्षण करता है। अध्ययन निष्कर्षित करता है कि यद्यपि क्षेत्रीय दलों के अत्यधिक प्रभाव ने कभी-कभी नीतिगत पंगुता और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, किंतु इसने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, प्रतिनिधिक, और संघात्मक स्वरूप प्रदान किया।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 10-07-2024
- **Accepted:** 25-07-2024
- **Published:** 30-08-2024
- **IJCRM:**3(4); 2024: 257-262
- **©2024, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Meena A K. The Role of Regional Parties During the Era of Coalition Governments (1989–2014): A Study. Int J Contemp Res Multidiscip. 2024;3(4): 257-262.

KEYWORDS: Coalition politics, regional parties, Indian federalism, National Front, National Democratic Alliance (NDA), United Progressive Alliance (UPA), policy-making, Bargaining Federalism.

© 2024 Dr. Ashok Kumar Meena. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विकास यात्रा में 1989 का वर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम तीन दशकों तक भारतीय राजनीति पर रजनी कोठारी द्वारा प्रतिपादित 'कांग्रेस प्रणाली' का एकछत्र साम्राज्य रहा। 1977 में जनता पार्टी का प्रयोग यद्यपि अल्पकालिक रहा, किंतु 1989 के 9वें लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति के बहुदलीय और प्रतिस्पर्धी ढाँचे को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। 1989 से लेकर 2014 तक के 25 वर्षों के कालखंड में भारत में किसी भी एकल राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत (272 सीटें) प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थिति ने केंद्र में 'गठबंधन सरकारों' (Coalition Governments) को अपरिहार्य बना दिया।

इस 25-वर्षीय कालखंड की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक घटना राष्ट्रीय स्तर पर 'क्षेत्रीय दलों' का तीव्र उभार था। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK), तेलुगु देशम पार्टी (TDP), समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), जनता दल यूनाइटेड (JD-U), तृणमूल कांग्रेस (TMC), और बीजू जनता दल (BJD) जैसे क्षेत्रीय दलों ने केंद्रीय सत्ता के समीकरणों को पुनर्रचित किया।

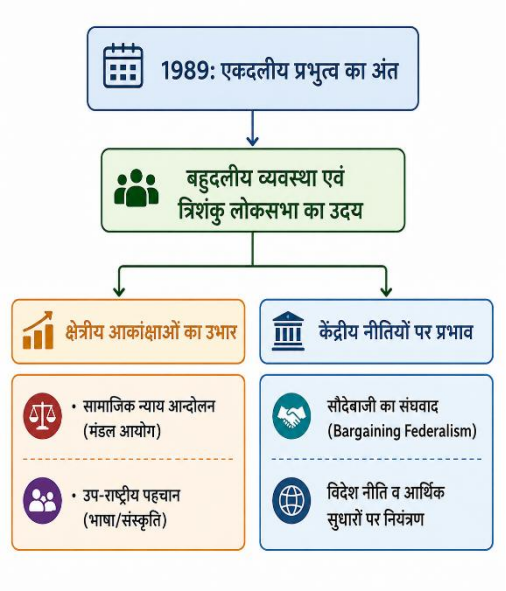

क्षेत्रीय दलों के इस उभार को योगेंद्र यादव ने 'भारतीय राजनीति का दूसरा लोकतांत्रिक उभार' कहा है, जिसमें पिछड़े वर्गों, दलितों, और प्रांतीय पहचानों ने राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श को नई दिशा दी। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषित करना है कि 1989-2014 के दौरान क्षेत्रीय दलों ने केंद्रीय स्तर पर सत्ता संरचना, संघवाद के स्वरूप, नीति निर्माण प्रक्रिया, तथा विदेश नीति को किस सीमा तक प्रभावित किया।

2. सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: एकदलीय प्रभुत्व से गठबंधन युग की ओर

2.1 एकदलीय प्रभुत्व का अवसान

स्वतंत्रता के पश्चात 1952, 1957, 1962, और 1967 के आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकाधिकार रहा। इस चरण को राजनीतिक विश्लेषकों ने 'एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली' के रूप में चिन्हित किया। किंतु 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में राज्यों में गैर-कांग्रेसवाद की लहर चली, जिसके परिणामस्वरूप 1967 के विधानसभा चुनावों में 9 राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। यह क्षेत्रीय शक्तियों का प्रथम संगठित प्रस्फुटन था।

2.2 सामाजिक-आर्थिक पुनर्गठन और मंडल-मंदिर राजनीति

1980 के दशक के अंतिम वर्षों में दो प्रमुख घटनाओं ने क्षेत्रीय दलों के लिए उर्वरा भूमि तैयार की:

1. **मंडल आयोग की सिफारिशें (1990):** अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय ने उत्तरी भारत में समाजवादी पार्टी (SP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), और जनता दल जैसे क्षेत्रीय शक्तियों को सामाजिक आधार प्रदान किया।
2. **राम जन्मभूमि आंदोलन (मंदिर राजनीति):** भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उभार के उत्तर में धर्मनिरपेक्षता के झंडाबरदार के रूप में क्षेत्रीय दलों ने स्वयं को प्रासंगिक बनाया।

1989-2014: भारतीय राजनीति का त्रिकोणीय और बहुदलीय समीकरण

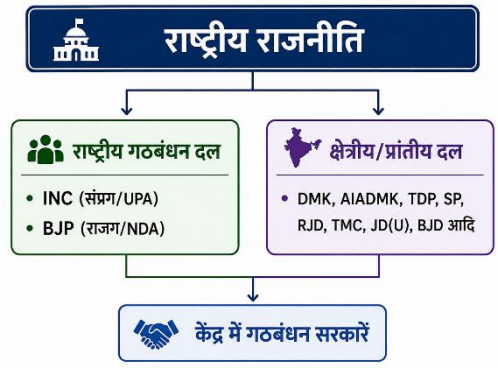

3. क्षेत्रीय दलों के उभार के प्रमुख कारण

1989 के पश्चात् क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक बनने के पीछे कई संरचनात्मक और सामाजिक कारक उत्तरदायी थे:

3.1 उप-राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक पहचान

भारत की भाषाई, सांस्कृतिक, और जातीय विविधता को केंद्रीयकृत राजनीतिक दल (जैसे कांग्रेस) पूर्णतः समोहित करने में असमर्थ रहे। तमिलनाडु में द्रविड़ पहचान (DMK/AIADMK), आंध्र प्रदेश में तेलुगु आत्म-स्वाभिमान (TDP), तथा पश्चिम बंगाल में बंगाली पहचान (TMC/वाम मोर्चा) ने प्रांतीय स्वायत्तता के विमर्श को जन्म दिया।

3.2 आर्थिक उदारीकरण और क्षेत्रीय असमानता

1991 के नए आर्थिक सुधारों (LPG) के बाद राज्यों के मध्य आर्थिक विकास की असमानता बढ़ी। संसाधनों, निजी निवेश, और केंद्रीय अनुदानों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को केंद्र पर दबाव बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसे क्षेत्रीय दलों ने कुशलतापूर्वक भुनाया।

© 2024 Dr. Ashok Kumar Meena. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3.3 राष्ट्रीय दलों का सांगठनिक क्षरण

राष्ट्रीय दलों (विशेषकर कांग्रेस) में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, अत्यधिक केंद्रीयकरण, और प्रांतीय नेतृत्व की उपेक्षा के कारण प्रांतीय स्तर पर जनाधार वाले क्षत्रपों (Regional Satraps) ने अपने पृथक राजनीतिक दल गठित कर लिए।

4. गठबंधन सरकारों के विभिन्न चरण और क्षेत्रीय दलों की भूमिका (1989-2014)

1989 से 2014 तक के 25 वर्षों को गठबंधन राजनीति के चार स्पष्ट चरणों में विभाजित करके विश्लेषित किया जा सकता है:

4.1 प्रथम चरण: राष्ट्रीय मोर्चा और अस्थिरता का दौर (1989-1991)

1989 के 9वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में **राष्ट्रीय मोर्चा (National Front)** सरकार का गठन हुआ, जिसे भारतीय जनता पार्टी (86 सीटें) और वाम मोर्चे (52 सीटें) का बाहर से समर्थन प्राप्त था।

- **विशेषता:** यह पहला अवसर था जब केंद्र में सरकार का अस्तित्व क्षेत्रीय और प्रांतीय घटकों (तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके, असम गण परिषद) के सामूहिक सहयोग पर टिका था।
- **भूमिका:** इस दौर में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन. टी. रामा राव ने राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय पटल पर एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

4.2 द्वितीय चरण: संयुक्त मोर्चा का दौर - 'किंगमेकर' के रूप में क्षेत्रीय दल (1996-1998)

1996 के 11वें लोकसभा चुनाव के बाद त्रिशंकु संसद की स्थिति में 13 क्षेत्रीय और वामपंथी दलों ने मिलकर **संयुक्त मोर्चा (United Front)** का गठन किया।

- **एच. डी. देवेगौड़ा एवं आई. के. गुजराल सरकारें:** कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी इन सरकारों में क्षेत्रीय दलों का पूर्ण नियंत्रण था।
- **संघीय मंत्रिमंडल की संकल्पना:** आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (TDP) ने संयुक्त मोर्चे के संयोजक के रूप में प्रधानमंत्री चयन में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसे भारतीय लोकतंत्र में प्रांतीय क्षत्रपों का चरम प्रभाव माना जाता है।

4.3 तृतीय चरण: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA: 1998-2004)

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग (NDA) का गठन भारतीय गठबंधन राजनीति का एक मील का पत्थर था। इसमें 20 से अधिक क्षेत्रीय दल सम्मिलित थे।

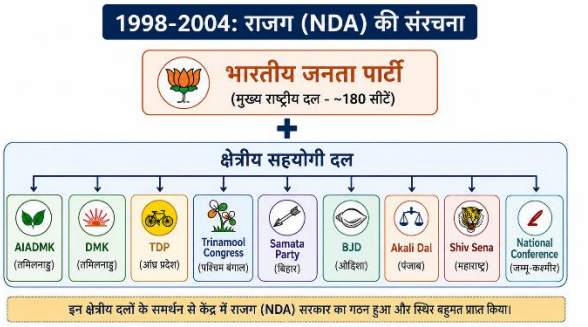

- **गठबंधन प्रबंधन:** भाजपा ने अपने कोर एजेंडे (धारा 370, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर) को अलग रखकर एक **साझा न्यूनतम कार्यक्रम (National Agenda for Governance)** तैयार किया।
- **क्षेत्रीय दलों का दबाव:** 1998 में एआईएडीएमके (जयललिता) द्वारा समर्थन वापस लेने पर वाजपेयी सरकार 1 वोट से गिर गई, जो क्षेत्रीय दलों की संहारक क्षमता (Veto Power) को दर्शाता है। 1999 में टीडीपी (चंद्रबाबू नायडू) ने बाहर से समर्थन देकर सरकार को स्थिरता प्रदान की, बदले में आंध्र प्रदेश के लिए भारी केंद्रीय सहायता प्राप्त की।

4.4 चतुर्थ चरण: संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA I एवं UPA II: 2004-2014)

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग (UPA) सरकार ने 10 वर्षों (2004-2014) तक शासन किया। यह चरण क्षेत्रीय दलों की संस्थागत भागीदारी और 'सौदेबाजी के संघवाद' का चरम बिंदु था।

- **संप्रग-I (2004-2009):** डीएमके, राजद, सपा, बसपा, और वामपंथी दलों के समर्थन पर आधारित था। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (रेल मंत्री) और डीएमके नेताओं को महत्वपूर्ण मलाईदार मंत्रालय (Lucrative Portfolios) मिले।
- **संप्रग-II (2009-2014):** तृणमूल कांग्रेस (ममता बनर्जी) और डीएमके (एम. करुणानिधि) की भूमिका अत्यंत आक्रामक रही। ममता बनर्जी ने खुदरा व्यापार में एफडीआई (FDI in Retail) और तीस्ता जल समझौते का कड़ा विरोध कर केंद्र सरकार की नीतियों को अवरुद्ध किया।

5. 1989-2014 की प्रमुख गठबंधन सरकारों का तुलनात्मक विश्लेषण

कालखंड	सरकार	प्रधानमंत्री	प्रमुख क्षेत्रीय घटक दल	स्थिरता एवं मुख्य प्रभाव
1989-1990	राष्ट्रीय मोर्चा	वी. पी. सिंह	टीडीपी, डीएमके, एजीपी	11 माह; मंडल आयोग लागू, अत्यंत अस्थिर
1990-1991	समाजवादी जनता पार्टी	चंद्रशेखर	जनता दल (एस)	4 माह; कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर निर्भर
1996-1997	संयुक्त मोर्चा	एच. डी. देवेगौड़ा	टीडीपी, डीएमके, टीएमसी, वाम मोर्चा	18 माह; क्षेत्रीय क्षत्रपों द्वारा 'किंगमेकर' की भूमिका
1997-1998	संयुक्त मोर्चा	आई. के. गुजराल	टीडीपी, डीएमके, सपा, वाम मोर्चा	11 माह; गुजराल सिद्धांत लागू
1998-1999	राजग (NDA-I)	ए. बी. वाजपेयी	AIADMK, समता पार्टी, बीजू जनता दल	13 माह; 1 वोट से सरकार का पतन
1999-2004	राजग (NDA-II)	ए. बी. वाजपेयी	TDP, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, अकाली दल	5 वर्ष पूर्ण; संस्थागत गठबंधन प्रबंधन का सफल मॉडल
2004-2009	संप्रग (UPA-I)	डॉ. मनमोहन सिंह	द्रमुक, राजद, एनसीपी, पीएमके	5 वर्ष पूर्ण; सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं (मनरेगा)
2009-2014	संप्रग (UPA-II)	डॉ. मनमोहन सिंह	तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, एनसीपी	5 वर्ष पूर्ण; नीतिगत पंगुता और क्षेत्रीय दलों की ब्लैकमेलिंग

© 2024 Dr. Ashok Kumar Meena. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

6. भारतीय संघवाद पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव

1989 से 2014 के दौर ने भारतीय संघवाद के स्वरूप को 'केन्द्राभिमुख' (Centripetal) से बदलकर 'सहकारी एवं सौदेबाजी के संघवाद' (Bargaining and Cooperative Federalism) में परिवर्तित कर दिया।

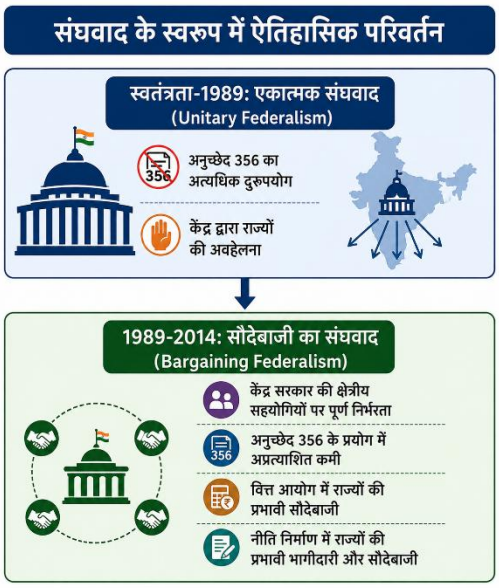

6.1 अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग में कमी

1989 से पूर्व केंद्र सरकारें विरोधी दलों की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)** का बारंबार दुरुपयोग करती थीं (उदा. इंदिरा गांधी शासनकाल)। किंतु 1989 के पश्चात् केंद्र में क्षेत्रीय दलों की निर्णायक उपस्थिति तथा एस. आर. बोम्मई मामला (1994) के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत सीमित हो गया।

6.2 वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism)

गठबंधन काल में क्षेत्रीय दलों ने अपने राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, कर छूट, और अवसंरचना परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजटों को प्रभावित किया:

- टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए 'साइबराबाद' और आईटी विकास हेतु केंद्रीय निधियों का बड़ा हिस्सा हासिल किया।
- राजद और जद (यू) ने बिहार के लिए 'विशेष राज्य का दर्जा' की मांग को केंद्रीय राजनीति के केंद्र में रखा।
- वित्त आयोग की सिफारिशों में राज्यों के हिस्से को बढ़ाने में क्षेत्रीय मुख्यमंत्रियों के दबाव समूह की बड़ी भूमिका रही।

7. सार्वजनिक नीति एवं विदेश नीति पर प्रभाव

1989-2014 के मध्य क्षेत्रीय दलों की भूमिका केवल सरकार बनाने और गिराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने भारत की आंतरिक सार्वजनिक नीतियों और विदेश नीति के संचालन को भी गहराई से प्रभावित किया।

7.1 विदेश नीति का क्षेत्रीयकरण (Regionalization of Foreign Policy)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति पर पारंपरिक रूप से केंद्र सरकार का एकाधिकार रहा है। किंतु 1989-2014 के कालखंड में प्रांतीय राजनीति ने विदेश नीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया:

1. **भारत-श्रीलंका संबंध (तमिलनाडु का प्रभाव):** डीएमके और एआईएडीएमके ने श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर केंद्र सरकार (राजग एवं संप्रग) पर लगातार दबाव बनाया। 2013 में संप्रग सरकार को यूएनएचआरसी (UNHRC) में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
2. **भारत-बांग्लादेश संबंध (पश्चिम बंगाल का प्रभाव):** 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (TMC) ने **तीस्ता जल बंटवारे समझौते** पर हस्ताक्षर करने से अंतिम समय में मना कर दिया, जिससे भारत-बांग्लादेश कूटनीतिक संबंधों में गम्भीर गतिरोध उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, **भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement)** में भी देरी हुई।
3. **भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2008):** वाम मोर्चे द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सपा (अखिलेश/मुलायम यादव) ने संप्रग सरकार को बचाकर इस ऐतिहासिक विदेश नीति समझौते को पारित कराने में निर्णायक भूमिका निभाई।

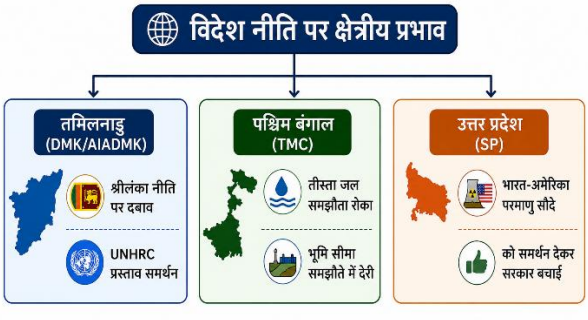

7.2 सामाजिक-आर्थिक नीतियों का निर्धारण

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):** संप्रग-I सरकार में वामपंथी दलों और क्षेत्रीय सहयोगियों के दबाव के कारण ऐतिहासिक जनकल्याणकारी नीतियां लागू हुईं।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का विरोध:** खुदरा क्षेत्र (Retail Sector) में एफडीआई का विरोध तृणमूल कांग्रेस और सपा दोनों ने किया, जिसके कारण संप्रग-II को कई आर्थिक सुधारों को टालना पड़ा या संशोधित करना पड़ा।

8. क्षेत्रीय दलों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन: गुण एवं दोष

गठबंधन युग में क्षेत्रीय दलों के आक्रामक प्रभाव ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव छोड़े।

8.1 सकारात्मक पहलू (Strengths)

1. **सच्चे संघवाद की स्थापना:** केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन स्थापित हुआ और राज्यों की आवाज को दिल्ली के गलियारों में अनुसुना करना असंभव हो गया।
2. **समावेशी लोकतंत्र (Inclusive Democracy):** समाज के वे वर्ग (ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, और भौगोलिक रूप से दूरस्थ

© 2024 Dr. Ashok Kumar Meena. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

क्षेत्र) जो पूर्व में उपेक्षित थे, उन्हें सत्ता संरचना में प्रत्यक्ष भागीदारी मिली।

3. **निरंकुशता पर अंकुश:** एकल दल के अधिनायकवाद (Authoritarianism) की संभावना समाप्त हुई। केंद्र सरकार को प्रत्येक नीति पर आम सहमति (Consensus) बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

8.2 नकारात्मक पहलू एवं चुनौतियाँ (Weaknesses)

1. **नीतिगत पंगुता (Policy Paralysis):** वैचारिक मतभेदों और क्षेत्रीय सहयोगियों की 'वीटो पावर' के कारण कई महत्वपूर्ण आर्थिक व प्रशासनिक सुधार वर्षों तक अटके रहे।
2. **अवसरवादी राजनीति और ब्लैकमेलिंग:** क्षेत्रीय दलों ने प्रायः राष्ट्रीय हित के स्थान पर संकीर्ण प्रांतीय या व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी। 'समर्थन वापसी' का भय दिखाकर मलाईदार मंत्रालयों की मांग करना आम बात हो गई।
3. **भ्रष्टाचार का संस्थागतीकरण:** 2G स्पेक्ट्रम घोटाला (द्रमुक नेताओं की संलिप्तता) और कोयला आवंटन घोटाला जैसे मामलों ने यह दर्शाया कि गठबंधन को बचाने के दबाव में मुख्य दल क्षेत्रीय सहयोगियों के भ्रष्टाचार के प्रति आंखें मूंद लेते थे।
4. **राजनीतिक अस्थिरता:** 1989 से 1999 के 10 वर्षों के भीतर भारत को 5 आम चुनावों और 7 प्रधानमंत्रियों का सामना करना पड़ा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और साख पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

9. 2014 के पश्चात का बदलाव और निष्कर्ष

9.1 2014: एकदलीय बहुमत की वापसी

वर्ष 2014 के 16वें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत (282 सीटें) प्राप्त किया। 2019 में इस बहुमत में और वृद्धि (303 सीटें) हुई। इसने 25-वर्षीय गठबंधन युग (1989-2014) का पटाक्षेप कर दिया और भारत 'एक-दल प्रभुत्व प्रणाली के पुनरुत्थान' (Resurgent One-Party Dominance) के दौर में प्रवेश कर गया।

10. निष्कर्ष

1989 से 2014 तक का गठबंधन सरकारों का दौर भारतीय लोकतंत्र के परिपक्व होने का कालखंड था। इस दौर में क्षेत्रीय दलों ने न केवल केंद्रीय सत्ता के संतुलन को संभाला, बल्कि भारत के विविध और विशाल ताने-बाने को राष्ट्रीय राजनीति में स्थान दिलाया।

यद्यपि क्षेत्रीय दलों की आक्रामक सौदेबाजी ने कभी-कभी सरकार की स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता को बाधित किया, किंतु इस युग का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि इसने भारत को एक अत्यंत विकेंद्रीकृत, संघात्मक और समावेशी राजनीतिक पहचान प्रदान की। 1989-2014 के दौरान निर्मित 'गठबंधन संस्कृति' ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान और समायोजन अत्यंत अनिवार्य है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल जेसी. भारत में गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय दल. आगरा: साहित्य भवन पब्लिकेशंस; 2009.
2. कोठारी रजनी. पॉलिटिक्स इन इंडिया. नई दिल्ली: ओरिएंट लोंगमैन; 1970.
3. कोठारी रजनी. स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी: इन सर्च ऑफ ह्यूमेन गवर्नेंस. दिल्ली: अजंता पब्लिकेशंस; 1988.
4. कविराज सुदीप्त. द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1997.
5. केनोयर जे, सिंह एमपी. कोएलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया: प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स. नई दिल्ली: मेंटो बुक्स; 2008.
6. गुहा रामचंद्र. इंडिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. लंदन: मैकमिलन; 2007.
7. चक्रवर्ती विद्युत. फॉरजिंग पावर: कोएलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2006.
8. हसन जोया. पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2002.
9. द्विवेदी एसएन. भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका. नई दिल्ली: अनामिका पब्लिशर्स; 2012.
10. पालशिकर सुहास. इण्डियन डेमोक्रेसी: द चेंजिंग ट्रेंड्स. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2014.
11. भार्गव राजीव. सेक्युलारिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2010.
12. मनोर जेम्स. इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया: ए स्टडी ऑफ द 1989 इलेक्शन्स. एशियन सर्वे. 1990;30(3):237-254.
13. यादव योगेंद्र. रीइन्वेंटिंग इंडिया: द सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. 1996;31(2):95-104.
14. यादव योगेंद्र, पालशिकर सुहास. फ्रॉम हंड्रेड टू मेनी: द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया (1989-2004). इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. 2006;41(51):5171-5183.
15. रुडोल्फ एलआई, रुडोल्फ एसएच. इन पर्सुइट ऑफ लक्ष्मी: द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ द इंडियन स्टेट. शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस; 1987.
16. वर्मा एके. डेवलपमेंट ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश. द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस. 2004;65(2):189-206.
17. शर्मा सीपी. भारतीय संघवाद और गठबंधन सरकारें. नई दिल्ली: अनामिका पब्लिशर्स; 2015.
18. शास्त्री संदीप, सूरी केसी, यादव योगेंद्र. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स: लोक सभा इलेक्शन्स 2004 एंड बियॉन्ड. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2009.
19. सिंह एमपी, सक्सेना रेखा. इण्डियन फेडरलिज्म: स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड ट्रेंड्स. नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग; 2011.

© 2024 Dr. Ashok Kumar Meena. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

20. हसन जोया. कांग्रेस आफ्टर इंदिरा: पॉलिसी, पावर एंड पॉलिटिकल चेंज (1984-2009). नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2011.
21. हेथकॉटे बी. रीजनल पार्टीज एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. जर्नल ऑफ कॉमनवेल्थ एंड कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स. 2001;39(1):45-62.

Creative Commons (CC) License
This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2024 Dr. Ashok Kumar Meena. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/